नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास दो बड़ी कंपनियां शुरू करेंगी परियोजनाएं

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 32 हजार करोड़ के निवेश से 15 हजार को रोजगार

कैबिनेट फैसला 1

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर पार्क के विकास प्रक्रिया को गति दे दी है। टॉर्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यमुना एक्सप्रेवे वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 28440 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वहीं, वामा सुंदरी इंवेस्टमेंट 3706 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कैबिनेट ने सोमवार को आईटी विभाग के इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इससे करीब 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने बताया कि टॉर्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इस परियोजना में 1000 लोगों को प्रत्यक्ष व 10 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी के इस निवेश पर यूपी सरकार की ओर से उसे 7037.50 करोड़ रुपये की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अन्य वित्तीय प्रोत्साहन उत्पादन शुरू होने पर मिलेंगे। यूपी सरकार के यह प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त हैं।

लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

300 करोड़ के निवेश से 4500 लोगों को रोजगार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में 2 संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत नोएडा में पैजेट इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण प्राइवेट कंपनी द्वारा 300 करोड़ के निवेश के रास्ता साफ हो गया है। इसके जरिए 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

वामा सुंदरी इंवेस्टमेंट कंपनी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर के निकट एक विशाल परियोजना स्थापित करेगी। इसमें 3706 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके जरिए 3780 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी 240000 यूनिट स्माल पैनल ड्राइवर आईसी, डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करेगी। कंपनी का फाक्सकान कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम होगा। 50 एकड़ में यह परियोजना लगेगी।

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पाने वाले को मिल सकेगी ग्रेच्युटी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स-1961 में 3 संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल, ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर व्यवस्था थी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद बिना ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त किए हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है। तो उसे देय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार के खाते में चली जाएगी।

पुलिस के लिए नए वाहन खरीदे जाएंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के लिए करोड़ों की लागत से 4 338 नए वाहनों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। कुछ समय पहले ही गृह विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था। इसमें पीएसी के लिए 25 वाहन और यूपी-112 के लिए 313 वाहन खरीदे जाएंगे। कैबिनेट में इन वाहनों को खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी। इसी तरह इसी कन्ट्रोल रूम में नए वाहन की खरीद भी स्वीकृत कर दी गई।